उत्तराखंड में पलायन, ग्रामीण विकास और महिला उद्यमिता: एक विवरणात्मक अध्ययन

डॉ॰ ललितमोहन पन्त, सह-प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
विकास जोशी, सह-प्राध्यापक, इतिहास विभाग
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी
डॉ॰ आशीष टम्टा, सह-प्राध्यापक, पर्यटन विभाग
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

1990 के दशक में जब से भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई तब से, भारत ने विकास की एक स्थिर दर देखी है और स्थिरीकरण-सह-संरचनात्मक समायोजन सुधार भारत के आर्थिक विकास के स्तंभ बन गए हैं। तभी से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में भारत अब दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से क्वांटम निवेश में वृद्धि के कारण अत्यधिक लाभ हुए हैं। व्यापक आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की स्थिति पूर्व-सुधार अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान सुसंगत रही है।

भारत में नियोजन के सबसे पुराने तरीकों में से एक मुख्य तरीका गरीबी और असमानता को कम करना रहा है। भारत में उदारीकरण के बाद से गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह प्रवृत्ति पहले दो दशकों में प्रत्यक्ष रही है। हालाँकि गरीबी को कम करने के मामलों में विभिन्न राज्यों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर दृष्टिगत है। लकड़वाला समिति (1951-52 से 2004-05 के लिए) और तेंदुलकर समिति (1993-94 से 2004-05 के लिए) गरीबी की माप करने वाली भारत में बनी प्रमुख समितियों में से एक है। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि साल 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 41% थी। आजादी के बाद से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'असमानता और गरीबी' एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 1993-94 और 2009-2010 के बीच गिन्नी गुणांक द्वारा मापी गई खपत के संदर्भ में असमानता शहरी क्षेत्रों में मामूली रूप से बढ़ी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1993-94 और 2004-05 के बीच बढ़ी और फिर 2009-10 में इसमें गिरावट दर्ज की गई।

इन सभी अनिश्चित तथा गंभीर कमियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक समेकित स्थिति में है। आज हमारा देश, विदेशी निवेश के एक प्रमुख गंतव्य स्थल के रूप में जाना

 ISSN 0975-735X

जाता है साथ ही यह बाहरी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओएफडीआई) को आकर्षित करने में सफल रहा है जो इसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। हालाँकि इन सबके बावजूद भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के संदर्भ में आज भी ग्रामीण भारत का विकास एक गहरी चिंता का विषय बना हुआ है।

भारत की अधिकांश आबादी (लगभग 65%) अभी भी गाँवों में निवास करती है जहाँ विषम गरीबी, स्वास्थ्य अवसरंचना में कमी और अशिक्षा जैसे मुद्दे केंद्र में बने हुए हैं। वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे अपने स्वयं के कल्याण कार्यक्रमों में भी प्रभावी रूप से भागीदारी करने में असमर्थ हैं साथ ही उनमें तकनीकी ज्ञान की भारी कमी है, और अक्सर उनके पास अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मानव पूँजी के अलावा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थितियों में इस अपर्याप्तता और असंगति का सामना करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक सुविचारित नीति की पहल की जाए जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। इन पहलों को महिलाओं की भागीदारी और उद्यमशीलता के संदर्भ में और भी अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ मामूली निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भी सृजित किया जा सके। एक ओर जहाँ शहरी संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी है, वहीं गाँवों में महिलाओं के पास भागीदारी हेतु न ही उचित कौशल और प्रशिक्षण उपलब्ध है और न ही गाँवों में कोई संगठित संरचना का विकास हो सका है। हालाँकि उदारीकरण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं परंतु वैश्वीकरण की घटना अपने-आपमें ग्रामीण विकास का कोई समाधान नहीं है। कोई भी राष्ट्र अपने सभी आयामों और दृष्टिकोणों में तभी विकास कर सकता है जब ग्रामीण विकास पर नए सिरे से जोर दिया जाए, वैसे भी गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी प्रकार का अभाव विकास में परिवर्तित नहीं होता सकता।

द्वैतवाद–भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक रूप से एक गहरा अंतर्संबंध है। वस्तुत: इन दोनों क्षेत्रों के बीच पूँजीगत और मानवीय संसाधनों का मुक्त आवागमन होना आवश्यक है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक के लिए सीमांत प्रतिफल समान होना चाहिएँ इससे जहाँ श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है वहीं फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी ज्यादा अंतराल उत्पन्न नहीं होता। हाल के दिनों में, अर्थव्यवस्था के अग्रणी जानकारों के मध्य ग्रामीण और शहरी विकास के बीच अंतर्संबंधों के विकास पर पुन: ध्यान दिया जाने लगा है और उन्होंने इस विषय पर नए सिरे से व्याख्या कर विश्व के सभी प्रमुख देशों का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया है।

हालाँकि इसके बावजूद भी सभी विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक द्वैतवाद अभी भी प्रबल रूप से मौजूद है। यह अर्थव्यवस्था में एक आधुनिक शहरी क्षेत्र के साथ-साथ पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र के अस्तित्व को परिलक्षित करता है। इस अंतर्द्वंद्व का एक प्रमुख कारण यह है कि भारत सहित कई विकासशील देशों ने अभी भी भारी औद्योगीकरण की नीति को साकार बनाने हेतु अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आधुनिक शहरी क्षेत्रों में संसाधनों तथा श्रम अधिशेष का मुक्त हस्तांतरण किया है। हालाँकि विकास की यह रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों के विरुद्ध और शहरी क्षेत्र के पक्ष में झुकी हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने व्यापक आर्थिक सुधार की शुरुआत की और यह सुधार नीतियाँ कुछ हद तक शहरी क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित

प्रतीत होती हैं। यह शहरी क्षेत्रों में हुए सुधार के प्रति झुकाव को अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक लक्षण में देखा जा सकता है, चाहे वह प्रति व्यक्ति आय की बात हो या फिर साक्षरता, शिक्षा, कौशल उन्नयन और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच से संबंधित मापक हों।

उपर्युक्त समग्र स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों यथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्पादन के कारकों को स्थिर कर समान करने के आधार पर एक ढाँचे को अपनाने का समर्थन करती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवागमन बाधा मुक्त हो अर्थात् सर्वप्रथम संसाधनों की आवाजाही को प्रभावित करने वाली विकृतियों को अर्थव्यवस्था से दूर किया जाए। यदि कोई देश अपनी नीतियों का क्रियान्वयन बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करता है तो उच्च दक्षता और अधिक समतावादी आय वितरण को प्राप्त किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर अधिक दक्षता और समानता आएगी वहीं सहक्रियता भी उत्पन्न होगी। शहरी पूर्वाग्रह में सुधार के लिए भी आवश्यक है कि कृषि से संबंधित प्रसंस्करण गतिविधियों में तेजी लाकर अधिक मूल्यवर्धन के साथ उच्च विकास को बढ़ावा दिया जाए। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी कम करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही बेहतर ग्रामीण-शहरी संबंध भी स्थापित होंगे।

अधिकांश विकासशील देशों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक है। चूँकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इस वजह से गरीबी की सघनता भी इस क्षेत्र में अधिक है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ उच्च विकास की नीतियों का क्रियान्वयन इन क्षेत्रों में किया जाए तो आवश्यक तौर पर गरीबी में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास की नीतियाँ कुछ हद तक पक्षपाती प्रतीत होती हैं क्योंकि वे शहरी क्षेत्र का पक्ष लेती हैं। हालाँकि वर्तमान समय में शहरी पूर्वाग्रह में कुछ सुधार हुआ है क्योंकि कृषि के लिए व्यापार की शर्तों ने विभिन्न सुधार प्रक्रियाओं को अपनाया है। फिर भी सरकारी निवेश में शहरी क्षेत्रों के प्रति अभी भी पक्षपात मौजूद है और इस पूर्वाग्रह सुधार के लिए आवश्यक है कि सरकार तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करना प्रारंभ करे। परिवहन और संचार जैसे ढाँचागत विकास जो कि गतिशील सुविधा के साथ-साथ बेहतर ग्रामीण-शहरी संपर्क स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं; का बेहतर विकास किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही आबादी के लिए बाजारों, रोजगार और सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके। आर्थिक लाभ से संबंधित अनुभवजन्य साक्ष्य भी इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान में निवेश करने से जहाँ एक ओर गरीबी के मामलों में कमी दृष्टिगत हुई है वहीं उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है।

विश्व के सभी देशों में द्वैतवाद की यह स्थिति आर्थिक द्वैतवाद के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मौजूद है। उदाहरणस्वरूप भारत में सामाजिक द्वैतवाद लंबे समय से अपनी जड़ें जमाए हुए है। जाति और लिंग व्यवस्था के रूप में इसे जाना और समझा जा सकता है। महिलाओं के संदर्भ में उनके परिश्रम के बावजूद उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है साथ ही कभी-कभार तो उन्हें बहुत अधिक अपमान और दमन का भी सामना करना पड़ता है। हालाँकि अब शनैः-शनैः इस विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। साथ ही ग्रामीण विकास और आत्म-सशक्तिकरण के लिए महिलाएँ गाँवों में उद्यमशीलता की पहल शुरू कर महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ भी निभा रही हैं। चूँकि वर्तमान सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता पैदा करने हेतु प्रयासरत हैं और इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में

 ISSN 0975-735X

उद्यमशीलता पैदा करने के लिए सरकार के पास महिलाओं के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ, प्रावधान और विशेष प्रोत्साहन भी शामिल हैं इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे सरकार की नीतियों का लाभ उठाएँ और स्वयं सरकारी नीतियों में शामिल होकर रोजगार पैदा करें।

प्रवास (माइग्रेशन)–प्रवासन ने हाल ही में संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय राज्य उत्तराखंड के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ इससे जुड़ा एक नया शब्द 'घोस्ट विलेज' अस्तित्व में आ चुका है। घोस्ट विलेज का तात्पर्य उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे गाँवों से है जिनकी संपूर्ण जनसंख्या पलायन कर चुकी है। इसके अलावा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा 'कृषि का नारीकरण' रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का पुरुष वर्ग जो कृषि गतिविधियों में संलग्न था अब रोजगार की तलाश में शहरी औद्योगिक केंद्रों में प्रवेश कर चुका है।

प्रवासन के हैरिस-टोडारो मॉडल ने इसकी अंतर्निहित गतिशीलता को समझने के लिए इसका गहन विश्लेषण किया है। यह मॉडल आर्थिक प्रणाली के दो क्षेत्रों यथा–ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रवास का विश्लेषण करता है। इन दो क्षेत्रों के बीच अंतर विभिन्न प्रकार के उत्पादित माल, उत्पादन की तकनीक और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित हैं। जहाँ एक ओर कृषि वस्तुओं का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र की विशिष्ट गतिविधि है वहीं निर्मित वस्तुओं का उत्पादन शहरी क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ वस्तुओं और श्रम बाजार दोनों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। श्रम बाजार में विभाजन न्यूनतम वेतन पर आधारित होता है जिसका निर्धारण राजनीतिक और संस्थागत रूप से होता है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी में लचीलापन देखने को मिलता है जो इस क्षेत्र के सीमांत उत्पादकता के बराबर है। इस मॉडल के अनुसार विनिर्मित वस्तुओं की तुलना में कृषि वस्तुओं की सापेक्ष कमी विनिर्मित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करती है। हैरिस और टोडारो के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक लंबी अवधी तक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रवासन पर, ग्रामीण श्रमिकों का निर्णय अपेक्षित शहरी मजदूरी/वेतन के अनुमान पर निर्भर करता है।

इस मॉडल की प्रमुख धारणाओं में से एक धारणा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवासियों का स्थानांतरण तब तक अनवरत रूप में होता रहेगा जब तक कि शहरी मजदूरी, ग्रामीण वेतन से अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें संतुलन की स्थिति तब ही उत्पन्न की जा सकती है जब ग्रामीण मजदूरी अपेक्षित शहरी मजदूरी के बराबर हो जाए। हैरिस टोडारो मॉडल एक एजेंट आधारित कंप्यूटेशनल मॉडल द्वारा परिष्कृत है जो कि श्रमिकों के ग्रामीण-शहरी विभाजन की प्रक्रिया को सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने का औपचारिक रूप देता है। इसमें एजेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कमाई के सर्वोत्तम स्थानों की खोज करते हैं। हैरिस-टोडारो मॉडल के अनुसार ग्रामीण-शहरी प्रवासन तब होता है जब अपेक्षित शहरी-मजदूरी ग्रामीण मजदूरी से अधिक हो जाएगी इसके अलावा होने वाले अन्य प्रवासन यथा–गैर-समन्वित और बिखरे हुए व्यक्तिगत प्रवासन का निर्णय स्थानीय जानकारी के आधार पर होता है जिसमें सकल नियमितता पाई जाती है। इस कंप्यूटेशनल मॉडल की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सिमुलेशन में एक समग्र पैटर्न प्रदर्शित होता है जो कि मूल हैरिस-टोडारो मॉडल में नहीं पाया गया है। यह समेकित पैटर्न दर्शाता है कि औसत मूल्य के आसपास शहरी मजदूरी में उतार-चढ़ाव की संभावना है, जिससे अनुमान लगया जा सकता है कि कभी यह वास्तविक शहरी मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त की जाने वाली मजदूरी से नीचे भी हो सकती है। इसी घटना को रिवर्स माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है और इसे कई विकासशील

देशों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया है।

इस एजेंट-आधारित हैरिस-टोडारो मॉडल की उत्तराखंड में प्रवासी पैटर्न के लिए निश्चित प्रासंगिकता है। इसका मुख्य कारण मजदूरी में अंतर है क्योंकि उत्तराखंड के गाँवों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और शहरी केंद्रों की अपेक्षा गाँवों में नाममात्र का वेतन प्राप्त होता है। हालाँकि यदि इसे वेतन और रहने लायक पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह अंतर कम हो जाता है। इसके साथ ही संशोधित मॉडल में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि अगर शहरी वेतन में गिरावट आती है तो रिवर्स माइग्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। इस रिवर्स माइग्रेशन को कोविड महामारी के आलोक में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, यह रिवर्स माइग्रेशन ऐसे समय में हुआ है जब शहरी केंद्रों में रोजगार के अवसर या तो कम हो गए हैं या मृतप्राय हो गए हैं, जिससे वापस ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ और इस रिवर्स माइग्रेशन के दौरान वापस आए प्रवासियों के पास विविध कौशल और नवोन्मेष विचारों का प्रवाह है जिसका उपयोग मानव संसाधनों के एक पुल के रूप में किया जा सकता है। क्योंकि ये वापस लौटे प्रवासी शहरी तौर-तरीकों और बाजारों से अच्छी तरह वाकिफ हैं अत: इसमें महिलाओं को केंद्र में रखकर उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन रिवर्स प्रवासियों को इस महामारी के दौरान अपने वास्तविक अहसासों की भी अनुभूति हुई है जिससे उनके भीतर अपने गाँवों में उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने की भावना भी बलवती हुई है।

कोविड-19 लॉकडाउन के बीच शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रवास कर चुके कई हजारों प्रवासी वापस उत्तराखंड वापस लौटे हैं और उत्तराखंड राज्य सरकार ने उन्हें ब्याज मुक्त ऋण, सब्सिडी, इको-टूरिज्म और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए मुफ्त बिजली की पेशकश करते हुए यहाँ वापस रहने और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिश की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में अलग से अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया है। राज्य के ग्रामीण विकास और प्रवासन आयोग द्वारा जारी एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 23 अप्रैल, 2020 तक कुल 59,360 लोग राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में वापस आ चुके थे, इनमें से 12,039 पौड़ी गढ़वाल में और 9,303 अल्मोड़ा से हैं। पौड़ी-गढ़वाल और अल्मोड़ा ये दोनों ही जिले प्रवास/पलायन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। राज्य में पलायन का आलम यह था कि 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य ही लगभग 3,50,000 निवासी राज्य से पलायन कर चुके थे और लगभग 1,048 गाँव निर्जन हो चुके हैं।

प्रवासियों की वापसी और उनके रहने से सामाजिक-आर्थिक असंतुलन को सुधारने में मदद मिल सकती है और निर्जन गाँवों को फिर से बसाया जा सकता है, इन निर्जन गाँवों में से कई गाँव तो सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित हैं।

उत्तराखंड में महिला उद्यमिता–किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उसकी सभ्यता के स्तर का व्यापक सूचक होती है। उद्यमशीलता से आर्थिक विकास होता है और इस गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ उलट गई है। उत्तराखंड की महिलाएँ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। उन्होंने राज्य गठन के संघर्ष में महत्त्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाने के साथ-साथ राज्य के विकास कार्यक्रमों, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो पूर्णत: महिलाओं पर ही केंद्रित है चाहे फिर

 ISSN 0975-735X

मुद्दा कृषि से संबंधित हो या फिर वन संरक्षण, मवेशियों की देखभाल, डेयरी उत्पादन या फिर पर्यावरण सरंक्षण का हो; उनकी भागीदारी को प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है।

इस बात में कोई दो राय नहीं की, उद्यमिता किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ है क्योंकि यह मूल्य और रोजगार सृजित करती है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और विकास तब तक एकतरफा ही रहेगा जब तक उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमशीलता को शामिल नहीं किया जाता। महिलाएँ जो कि विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं; आज भी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भारी असमानता है। उनकी स्थिति को सही करने का एकमात्र उपाय उन्हें उद्यमिता में शामिल करना है। डेल द्वारा वर्ष 2015 में किए गए एक अध्ययन में कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इन मापदंडों में शामिल हैं–कारोबार के लिए माहौल, संसाधनों तक लिंग आधारित पहुँच, महिलाओं का नेतृत्व और कानूनी अधिकार, उद्यमिता के लिए पाइप लाइन और संभावित महिला उद्यमी नेता। विभिन्न देशों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूके और यूएसए ने महिला उद्यमिता क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है, जबकि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान ने एशियाई देशों में सबसे कम स्कोर किया है। (वैश्विक महिला उद्यमी लीडर्स स्कोरकार्ड 2015) वर्तमान समय में विश्व के तमाम देशों में से भारत में शिक्षित युवा आबादी की संख्या सर्वाधिक है। शैक्षणिक सुविधाओं के मद्देनजर उत्तराखंड राज्य के निवासियों को विविध कौशल सीखने के मौके अधिक उपलब्ध हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में साक्षरता और शिक्षा का स्तर उत्तराखंड राज्य में बहुत अधिक है। इसके अलावा भी पूरे देश में विभिन्न अभियानों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे की स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया आदि।

वर्तमान समय में महिला उद्यमिता के क्षेत्र में शिक्षाविदों द्वारा भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। यह क्षेत्र दुनियाभर में जोर पकड़ रहा है और भारत भी इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। महिलाएँ जो कि आबादी के 50% भारांश का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह भी सच है कि यहाँ के पितृसत्तात्मक समाज में आर्थिक विकास की मुख्य धारा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लेकिन समय की जरूरत है कि महिलाओं में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। उत्तराखंड में, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने बुनियादी खाद्य प्रसंस्करण और ऊन बुनाई जैसी पारंपरिक गतिविधियों में कदम रखा है। उत्तराखंड के कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल में अनुकरणीय प्रदर्शन के कई उदाहरण हैं। हालाँकि अभी भी मूल्य संवर्द्धन और कवरेज का दायरा बढ़ाने की जरूरत है साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ाना होगा ताकि अधिक वैल्यू एडिशन हासिल किया जा सके। नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का संगठित विपणन एक सीमा के अधीन है। इसके चलते वस्तुओं का मूल्यवर्धन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी की उच्च दर है और व्यावसायिक गतिविधियों में उनकी प्रमुख भूमिका है। यह इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक क्षमता है, आवश्यकता है कि इसे निवेश के माध्यम से संस्थागत रूप से वित्तपोषित किया जा सके। महिलाओं द्वारा हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का काम भी किया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में उनकी निपुणता अधिक होती है, हालाँकि इसके लिए कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी जिसके लिए संस्थागत मदद माँगी

जा सकती है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक और अवसर आतिथ्य क्षेत्र के रूप में भी उभरा है, जहाँ महिलाएँ वापस लौटने वाले लोगों की मदद से परित्यक्त घरों को होमस्टे में बदलने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि उत्क्रमित प्रवासियों में से अधिकांश व्यक्तियों की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है और इनमें से अधिकांश लोग काफी कम वेतन पर आतिथ्य क्षेत्र में काम भी कर चुके हैं। साथ ही इस माध्यम से जहाँ वे अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा पाएँगे, वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष–उदारीकरण के बाद से भारत का विकास मार्ग संतोषजनक रहा है, लेकिन इसने सही अर्थों में विकास को हासिल नहीं किया है। यह विकास ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा है जैसा कि द्वैतवादी प्रतिमानों से परिलक्षित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अभाव और सामाजिक द्वैतवाद अधिक स्पष्ट है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है। ग्रामीण भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएँ पूर्णत: मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगी। चूँकि विकास से संबंधित नीतियाँ मुख्यत: उद्योगों से संबंधित होती हैं और इनमें एक प्रकार से शहरी पूर्वाग्रह पहले से ही शामिल होते हैं, इसके अलावा किसी शहरी कारोबारी माहौल को गाँवों में स्थापित भी नहीं किया जा सकता इसलिए आवश्यक है कि कृषि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मूल्यवर्धन वाली गतिविधियों की भी शुरुआत की जाए।

उत्तराखंड के संदर्भ में रोजगार की तलाश में नगरीय औद्योगिक केंद्रों की ओर बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है जो कि लाभ की दृष्टि से बेहतर है। राज्य में उद्यमी उपक्रम भी मौजूद हैं जो की बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। महिला उद्यमिता के इस क्षेत्र को प्राथमिक कृषि पर आधारित गतिविधियों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ावा देने और विविधीकरण की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप रिवर्स माइग्रेशन के चलते महिलाओं की भागीदारी के साथ नए उद्यमशीलता उद्यमों को शुरू करने का एक बेहतर मौका लोगों के पास उपलब्ध है जिसमें वापस लौटने वाले प्रवासियों के कौशल और ज्ञान का उपयोग भी किया जा सकता है।

संदर्भ

1. M.S. Ahuluwalia, (2002) , Economic Reforms in India Since 1991: Has Gradualism Worked. Journal of Economic Perspectives, Vol: 16, No. 03, P. 67-88
2. M.S.Ahuluwalia, (2011), Prospects and Policy Challenges in the Twelfth Plan, Economic and Political Weekly, Vol. 46, No. 21, P. 88-105
3. L.Aquino, S.J Jaylson And T.T.P. Penna, (2006), A Harris-Todaro Agent Based- Model to Rural-Urban Migration. Brazilian Journal of Physics, Vol- 36, Sao Paulo.
4. N. Bertaux And E. Crable, (2007) , Learning About Women, Economic Development, Entrepreneurship and the Environment in India. A Case Study, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 12, No. 04, P. 467-478.
5. S.S.Bhalla (2011) , Inclusion and Growth in India: Some Facts, Some Conclusions. Asia Research Center Working Paper 39, London School of Economics and Political Science.
6. N.R. Bhanumurthy and A. Mitra, (2003) , Declining Poverty in India: A Decompositions Analysis, Working Paper-70 Institute of Economic Growth, New Delhi
7. C. Brush, A. Bruin And F.Welter, (2009), A Gender-Aware Framework for Female Entrepreneurship, International Journal of Gender & Entrepreneurship. Vol.01, No.